नाखुश घटक दलों के बदले सुर

हाल के दिनों में भाजपा के कई अहम सहयोगी दल नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करने में मुखर हुए हैं

अर्चिस मोहन

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक प्रमुख सहयोगी दल तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) ने शुक्रवार को कहा कि वह केंद्रीय बजट से असंतुष्ट जरूर है लेकिन पार्टी तुरंत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) से अलग होने का फैसला नहीं करेगी। वहीं भाजपा के एक प्रमुख दल शिवसेना ने कहा कि यह देखना बाकी है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जो बजट पेश किया है उस पर जमीनी स्तर पर कितना अमल किया जाएगा। इन दो दलों के बयान से भाजपा के नेतृत्व वाले राजग में असंतोष के स्वरों में और उभार आया है। हाल के दिनों में भाजपा के कई अहम सहयोगी दल नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करने में ज्यादा मुखर हुए हैं।

बात केवल शिवसेना या तेदेपा तक ही सीमित नहीं है बल्कि बिहार में भाजपा के सहयोगी दल ने भी पार्टी को नजरअंदाज किए जाने से जुड़ी चिंताओं पर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने दावा किया कि उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (आरएलएसपी) और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) की उनकी पार्टी के साथ बातचीत चल रही थी। कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी की लोकसभा में तीन सीटें हैं जबकि मांझी की पार्टी बिहार में जनता दल (यूनाइटेड)-भाजपा के गठबंधन का एक हिस्सा है। गुरुवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट की तारीफ की लेकिन उनकी पार्टी ने लोकसभा और बिहार विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने के प्रधानमंत्री के आग्रह पर अमल करने की संभावनाओं को सीधे तौर पर खारिज कर दिया। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख प्रकाश सिंह बादल ने भी वित्त मंत्री के बजट को किसानों के हित में बताया लेकिन उनकी पार्टी भी लोकसभा चुनावों के लिए अपने विकल्पों का आकलन कर रही है। शिवसेना के संजय राउत ने कहा कि गुजरात चुनाव तो महज एक ट्रेलर था और राजस्थान उपचुनाव में भाजपा की हार का इंटरवल है। उन्होंने कहा, 'अब हम पूरी फिल्म 2019 में देखेंगे। लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने के फैसले में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा।' राउत ने कहा कि मोदी सरकार का आखिरी बजट कागजी दस्तावेज के रूप में पढ़ने के लिए अच्छा था। उन्होंने कहा, 'अगर इस बजट को किसानों के लिए हितकारी बताया जा रहा है तो हमें इसके जमीनी असर का आकलन करने के लिए कम से कम एक महीने का इंतजार करना होगा ताकि यह अंदाजा मिले कि इससे महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या रोकने में मदद मिली या नहीं।'

तेदेपा ने कहा कि यह 'असंतुष्ट' करने वाला बजट था क्योंकि वित्त मंत्री ने राज्य की जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया लेकिन पार्टी गठबंधन से अभी नहीं हटेगी। पार्टी के सूत्रों ने बताया कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को अमरावती में पार्टी की समन्वय समिति की बैठक में इस बात के संकेत दिए।

सूत्रों का कहना है कि बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि बजट प्रस्तावों में राज्य के साथ अन्याय हुआ। तेदेपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने ऑफ रिकॉर्ड बताया कि बजट में राज्य को नजरअंदाज किए जाने के बाद पार्टी के जिला इकाई प्रमुखों सहित लगभग सभी लोग चाहते हैं कि तेदेपा भाजपा के साथ अपना गठबंधन खत्म कर दे। तेदेपा के सूत्रों का कहना है कि नायडू के मुताबिक उपचुनाव के नतीजे स्पष्ट रूप से यह संदेश देते हैं कि अगर सरकार सही नहीं होगी तो लोग अपना समर्थन वापस ले सकते हैं।

ऐसा बताया जा रहा है कि नायडू ने इस बात पर गंभीर असंतोष जताया कि केंद्र ने बजट में राज्य को नजरअंदाज कैसे कर दिया। सूत्र के मुताबिक नायडू ने कहा कि बेंगलूरु, मुंबई और अहमदाबाद को विभिन्न परियोजनाओं के लिए बड़ा आवंटन मिला लेकिन राज्य की किसी भी परियोजना के लिए कोई आवंटन नहीं हुआ जिनमें विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम मेट्रो रेल शामिल है।

रिश्ते में खटास!

- भाजपा के प्रमुख सहयोगी दल शिवसेना और तेदेपा ने बजट पर जताया असंतोष
- तेदेपा ने राजग से अलग होने की अटकलें कीं खारिज
- बिहार में भी आरएलएसपी और जीतन राम मांझी की पार्टी में असंतोष के स्वर
- नीतीश ने बजट की तारीफ की पर पार्टी साथ चुनाव कराने के पक्ष में नहीं

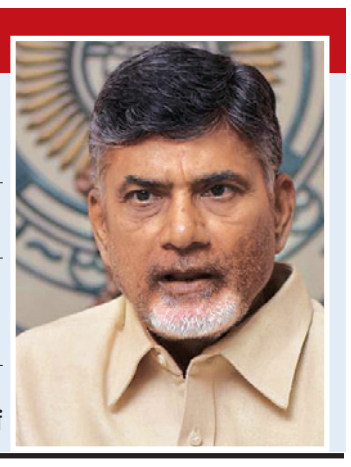

अंतरिक्ष विभाग को आवंटन थोड़ा कम

टी ई नरसिम्हन

केंद्र ने 2018-19 के लिए बजट में अंतरिभ विभाग (डीओएस) के लिए लगभग 89.63 अरब रुपये आवंटित किए हैं। हालांकि यह आवंटन पिछले साल के 90.92 अरब रुपये की तुलना में थोड़ा कम है, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि इसे इसरो द्वारा निजी उद्योगों के साथ भागीदारी करने और एंट्रिक्स के बढ़ते राजस्व के तौर पर देखा जाना चाहिए।

हालांकि बजट भाषण में पिछले वर्ष कई उपलब्धियां हासिल करने वाले अंतरिक्ष विभाग के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया, लेकिन आउटकम फ्रेमवर्क फॉर स्कीम्स 2018-19 के अनुसार यह आवंटन प्रक्षेपण यान और उपग्रह तैयार करने से जुड़ा होगा जिससे देश को खासकर आपदाओं के दौरान मदद मिलेगी। 89.63 अरब रुपये में से, बड़ा हिस्सा या लगभग 65.76 अरब रुपये शोध एवं विकास और अंतरिक्षयान तथा प्रक्षेपण यान जुटाने के लिए शामिल हैं। इन यानों में तीन भूमि पर्यवेक्षण यान, चार पीएसएलवी उड़ानें, एक जीएसएलवी एमके-3 फ्लाइट और एक जीएसएलवी शामिल हैं। केंद्र उन्नत क्षमताओं के साथ ईओ सेवाएं लगातार मुहैया कराने के लिए अंतरिक्ष संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना चाहता है। वह घरेलू और वाणिज्यिक उपग्रहों के लिए प्रक्षेपण सेवा का परिचालन भी सुनिश्चित करना चाहता है। साथ ही वह चाहता है कि देश 2.5-3 और 4 टन श्रेणी के संचार उपग्रह को प्रक्षेपित करने में आत्मनिर्भर बने। अंतरिक्ष विज्ञान मिशन और अंतर्ग्रहीय अभियान के लिए 2.3 अरब रुपये भारत के लूनर मिशन/चंद्रयान-2, आदित्य एल1 मिशन के लिए 2 उप-प्रणालियों की तैयारी के लिए निर्धारित किए गए हैं।

- अंतरिक्ष विभाग के लिए इस बार बजट में किया गया है 89.63 अरब रुपये का आवंटन
- आवंटित बजट का बड़ा हिस्सा शोध एवं विकास और अंतरिक्षयान और प्रक्षेपण यान जुटाने पर खर्च किया जाएगा

वहीं 4.11 अरब रुपये वर्ष के दौरान दो संचार उपग्रहों को पूरा करने और पेश करने के लिए निर्धारित किए गए हैं। इससे दूरसंचार/टेलीविजन प्रसारण, आपदा संचार, टेली-एजूकेशन और टेली-हेल्थ सेवाओं को मदद मिलेगी। एयरोस्पेस ऐंड स्पेस में विश्लेषक एवं स्वतंत्र कंसल्टेंट (रक्षा) रतन श्रीवास्तव ने उपग्रहों और प्रक्षेपणयान के लिए निजी क्षेत्र की मदद ली है, जिसकी वजह से इसकी पूंजी लागत में कमी आएगी। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इसरो की वाणिज्यिक इकाई एंट्रिक्स कॉरपोरेशन पर भी विचार करना चाहिए जिसका राजस्व सालाना आधार पर बढ़ा है।

2016-17 में एंट्रिक्स का कारोबार बढ़कर 19.23 अरब रुपये पर पहुंच गया जो एक साल पहले समान अवधि के दौरान 18.60 अरब रुपये था। इसका कर-बाद लाभ (पीएटी) बढ़कर 2.09 अरब रुपये रहा है जबकि पूववर्ती वर्ष के दौरान यह आंकड़ा 2.05 अरब रुपये पर था।

इसरो ने हर साल उपग्रह प्रक्षेपण में तेजी लाने के लिए अपनी क्षमता बढ़ाई है। शुरू में इसरो हर साल 2-3 प्रक्षेपण करता था, फिर पिछले कुछ वर्षों में इसे बढ़ाकर 4-5 किया गया और मौजूदा समय में यह सालाना 7 है। इसे बढ़ाकर 23 किए जाने की योजना है।

निर्वाचन आयोग के आवंटन से चुनाव की अटकलें

साहिल मक्कड़

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2018-19 के बजट में चुनाव आयोग को देश में चुनाव कराने के लिए 110 फीसदी ज्यादा बजट दिया है। इससे इन अटकलों में तेजी आई कि केंद्र सरकार अगले साल मार्च में होने वाले आम चुनावों को पहले भी करा सकती है। जेटली ने चुनाव कराने के मकसद से 2018-19 के लिए 2.48 अरब रुपये की राशि दी है। 2017-18 के संशोधित अनुमान के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष में चुनाव आयोग ने 1.18 अरब रुपये खर्च किए थे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की वकालत करते रहे हैं। बजट सत्र की शुरुआत में संसद के संयुक्त सत्र के संबोधन के दौरान भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक साथ चुनाव कराने की मांग रखी थी। लेकिन लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने के लिए संविधान और कई कानूनों में पहले संशोधन कराना होगा जिनके तहत देश में चुनाव होता है। सरकार ने चुनाव आयोग के कुल बजट में 41 फीसदी तक की बढ़ोतरी की है। 2018-19 में निर्वाचन आयोग के लिए जेटली ने 2.67 अरब रुपये का बजट तय किया है जबकि 2017-18 के संशोधित अनुमान के मुताबिक निर्वाचन आयोग का कुल खर्च करीब 1.89 अरब रुपये था। अतिरिक्त बजटीय आवंटन की वजह से ये अटकलें लगने लगीं कि आम चुनाव भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के साथ ही होंगे। इन तीन राज्यों में इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं जबकि मणिपुर, नगालैंड और त्रिपुरा में इस साल मार्च में चुनाव होने हैं। कर्नाटक में अप्रैल में चुनाव होंगे। हालांकि सरकार का कहना है कि बजटीय आवंटन निर्वाचन आयोग के लिए अतिरिक्त जमीन की खरीद के मकसद से किया गया है। सरकार ने अपने बजट दस्तावेज में कहा, 'यह प्रावधान निर्वाचन आयोग के संस्थान संबंधी खर्च के लिए और इसमें इंडिया इंटरनैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी ऐंड इलेक्शन मैनेजमेंट कैंपस का निर्माण और निर्वाचन आयोग के लिए एक अतिरिक्त इमारत तैयार करने के लिए जमीन की खरीद शामिल है। इसमें कंप्यूटर आदि उत्पादों की खरीद, आयोग के प्रबंधन और राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता अभियान से जुड़ी योजनाओं के लिए प्रावधान शामिल है।'

चुनाव आयोग का बजट

	2017-18 (सं.अ.)	2018-19 (ब.अ.)	प्रतिशत में बदलाव
निर्वाचन आयोग का कुल बजट (अरब रुपये में)	1.89	2.67	41.3
चुनावों के लिए (अरब रुपये में)	1.18	2.48	110.2

सं.अ.: संशोधित अनुमान, ब.अ.: बजट अनुमान, *स्रोत: केंद्रीय बजट*

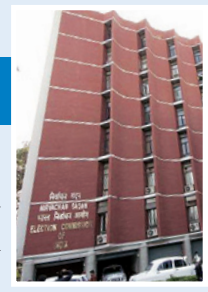

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक

www.bankofbaroda.co.in

बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, मुंबई

प्रस्ताव हेतु अनुरोध (संदर्भ : आरएफ़पी : सीआईएडी : 110/1)

बैंक ऑफ बड़ौदा विशेषीकृत इंटीग्रेटेड ट्रेजरी शाखा, मुंबई के लिए समवर्ती लेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करता है.

विस्तृत विवरण बैंक की वेबसाइट **www.bankofbaroda.co.in** के निविदा खंड पर उपलब्ध हैं.

यदि निविदा में परिशिष्ट सहित कोई संशोधन/आशोधन/परिवर्तन होगा तो उसे केवल बैंक की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा. बोलीकर्ता प्रस्ताव को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने से पहले इसे अवश्य देख लें.

उपर्युक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख : 22 फरवरी, 2018 दोपहर 2.00 बजे तक है.

दिनांक : 02 फरवरी 2018 **प्रमुख**
स्थान : मुंबई **(आंतरिक लेखा -परीक्षा)**

(104/17-18)

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक

www.bankofbaroda.co.in

निविदा सूचना

बैंक ऑफ़ बड़ौदा 5 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियों को सूचीबद्ध करने हेतु निविदा आमंत्रित करता है.

विवरण बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.co.in के 'निविदा खण्ड' पर उपलब्ध हैं.

निविदा में परिशिष्ट सहित कोई संशोधन/ सुधार/ परिवर्तन को केवल बैंक की वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा. इच्छुक बोलीकर्ता प्रस्ताव को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने से पहले इसे अवश्य देख लें.

उपर्युक्त निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख: 26 फरवरी, 2018 दोपहर 2.00 बजे तक है.

स्थान : मुंबई **महाप्रबंधक**
दिनांक : 03 फरवरी, 2018 **(मार्केटिंग, डब्ल्यूएमएस एवं कार्पोरेट जनसंचार)**

106/17-18

APPOINTMENTS

बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लिमिटेड
Baroda Global Shared Services Ltd.
(बैंक ऑफ़ बड़ौदा की एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी)

पंजीकृत कार्यालय – 5 वां तल, बड़ौदा सन टॉवर, सी-34, जी-ब्लॉक
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051

भर्ती

अपने प्रस्तावित केंद्र हैदराबाद में निम्नलिखित पदों के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करता है:-

1) इकाई(यूनिट) प्रबंधक
2) टीम लीडर/ पर्यवेक्षक (खुदरा आस्ति/ वैश्विक व्यापार सेवाएं/ धन प्रेषण)
3) टीम सदस्य- मानव संसाधन
4) टीम सदस्य- प्रशिक्षण एवं विकास (देयताएं/आस्तियां/व्यापार वित्त)
5) टीम सदस्य- वैश्विक व्यापार सेवाएं/धन प्रेषण
6) टीम सदस्य- खुदरा आस्तियां- प्रोसेस ओनर
7) टीम सदस्य- खुदरा देयताएं/ आस्तियां- सत्यापनकर्ता
8) टीम सदस्य- खुदरा देयताएं- वैलिडेटर

उपर्युक्त से संबंधित अन्य विवरण के लिए www.bgss.in का कॅरियर खंड देखें.

यदि कोई परिशिष्ट/संशोधन होगा तो उसे केवल www.bgss.in पर अधिसूचित किया जाएगा. अभ्यर्थी अपना आवेदन अंतिम रूप से प्रस्तुत करने से पहले इसे अवश्य देख लें. उपर्युक्त पदों के लिए अंतिम तारीख 26.02.2018 है.

हस्ता/-
स्थान- मुंबई प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
दिनांक 02.02.2018 बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लि.

105/17-18

एक राष्ट्र ग्रिड फ्रीक्वेन्सी

राष्ट्र विकास की धमनियाँ

पावरग्रिड

पावरग्रिड

31 दिसंबर, 2017 को समाप्त तिमाही और नौमाही के लिए एकल अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का उद्धरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.12.2017 को समाप्त तिमाही (अलेखापरीक्षित)	31.12.2016 को समाप्त तिमाही (अलेखापरीक्षित)	31.12.2017 को समाप्त नौमाही (अलेखापरीक्षित)	31.12.2016 को समाप्त नौमाही (अलेखापरीक्षित)	31.03.2017 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)
1.	प्रचालन से कुल आय (शुद्ध)	7506.95	6629.76	21941.14	19004.50	25716.54
2.	कर पूर्व लाभ (विनियामक स्थगन खाते में शेष में संचलन सहित)	2640.45	2500.62	7918.62	7145.07	9569.76
3.	अवधि हेतु कर पश्चात् लाभ, विनियामक स्थगन खाता शेष में संचलन से पूर्व	2142.76	1938.41	6185.60	5616.77	7450.22
4.	अवधि हेतु कर पश्चात् लाभ	2040.83	1930.02	6234.28	5603.79	7520.15
5.	कर के बाद निवल लाभ और अन्य व्यापक आय को मिलाकर कुल व्यापक आय	2035.95	1900.31	6264.92	5589.76	7569.98
6.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी (शेयर का अंकित मूल्य ₹10/- प्रत्येक)	5231.59	5231.59	5231.59	5231.59	5231.59
7.	आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर) तुलनपत्र में दर्शाए गए रूप में					44575.66
8.	प्रति इक्विटी शेयर अर्जन, विनियामक की स्थगन खाता शेष में संचलन सहित (प्रति शेयर का मूल्य ₹10/-): मूल और तनुकृत (₹)	3.90	3.69	11.92	10.71	14.37
9.	प्रति इक्विटी शेयर अर्जन, विनियामक की स्थगन खाता शेष में संचलन छोड़कर (प्रति शेयर का मूल्य ₹10/-): मूल और तनुकृत (₹)	4.09	3.71	11.82	10.74	14.24

टिप्पणियां:

1. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेन्ज में जमा किए गए तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का उद्धरण है। वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप हमारी वेबसाइट **http://www.powergridindia.com** के निवेशक संबंध खण्ड में तथा बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेन्ज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट्स **http://www.bseindia.com** तथा **http://www.nseindia.com** के कॉर्पोरेट खण्ड में उपलब्ध है।
2. (क) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने विद्युत अधिनियम, 2003 के धारा 178 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए ब्लॉक अवधि 2014-19 के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ के निर्धारण के लिए 21 फरवरी, 2014 के आदेश के माध्यम से ''सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियमावली, 2014'' अधिसूचित किया है।
   (ख) कंपनी ने तिमाही एवं नौमाही के दौरान ट्रांसमिशन आय को निम्नानुसार मान्यता दी है:
   (i) सीईआरसी द्वारा जारी अंतिम टैरिफ आदेश के अनुसार तिमाही के लिए ₹6086.48 करोड़ (संगत पूर्व तिमाही ₹5446.45 करोड़) और नौमाही के लिए ₹17396.02 करोड़ (संगत पूर्व नौमाही ₹16047.36 करोड़)।
   (ii) तिमाही के लिए ₹1090.83 करोड़ (संगत पूर्व तिमाही ₹760.39 करोड़) तथा नौमाही के लिए ₹3549.43 करोड़ (संगत पूर्व नौमाही ₹1943.41 करोड़) उन ट्रांसमिशन आस्तियों के संबंध में जिनके लिए सीईआरसी टैरिफ विनियमावली और ऐसे मामले में अन्य आदेशों के अनुसार अंतिम टैरिफ आदेश अभी जारी किया जाना शेष है।
   (ग) सीईआरसी द्वारा जारी अंतिम आदेशों के परिणामस्वरूप ट्रांसमिशन आय में 31 दिसंबर, 2017 को समाप्त तिमाही और नौमाही के लिए क्रमशः ₹69.99 करोड़ (घटाव) और ₹48.19 करोड़ (घटाव) पूर्व के वर्षों से संबंधित सम्मिलित हैं। (पिछले वर्ष की तिमाही और नौमाही के लिए संगत आंकड़े क्रमशः ₹15.78 करोड़ (घटाव) और ₹93.16 करोड़ (बढ़ोतरी))
3. कर्मचारी हितलाभ व्यय में तिमाही हेतु ₹140.88 करोड (संगत पूर्व तिमाही शून्य) और नौमाही के लिए ₹239.93 करोड़ (संगत पूर्व नौमाही शून्य) (निर्माण के दौरान व्यय को घटाने के बाद) कर्मचारियों के वेतन संशोधन जो कि 1 जनवरी, 2017 से लागू होना है, भी शामिल है।
4. करों, कर्मचारी लाभों के प्रावधान और अन्य आकस्मिक खर्चों के लिए प्रावधान को अनुमान के आधार पर लिया गया है।
5. निदेशक मंडल ने 1 फरवरी, 2018 को हुई अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए प्रति शेयर (प्रत्येक ₹ 10/- अंकित मूल्य) ₹2.45 के अंतरिम लाभांश की घोषणा की है।
6. उपरोक्त वित्तीय परिणाम की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा तथा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन 1 फरवरी, 2018 को आयोजित अपनी संबंधित बैठकों में किए गए हैं।
7. उपरोक्त परिणामों की समीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा सेबी (सूचीकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत कर ली गई है।

कृते और **पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमि.**
की ओर से
हस्ता./-
(आई.एस. झा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 1 फरवरी, 2018

India's Best Companies To Work For 2017 GREAT PLACE TO WORK The Economic Times

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
पंजीकृत कार्यालय : बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016
केन्द्रीय कार्यालय: ''सौदामिनी'', प्लाट नं. 2, सेक्टर-29, गुरूग्राम, हरियाणा-122001
CIN: L40101DL1989GOI038121

हमें फॉलो करें: YouTube www.powergridindia.com

महत्वपूर्ण सूचना: सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी ई-मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों/कंपनी के रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट (कार्वी) के पास अपडेट करें, जिसे भविष्य में ई-मेल के माध्यम से आधिकारिक दस्तावेज भेजने में उपयोग किया जायेगा।

एक 'नवरत्न' कंपनी

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon !

डिजिटल बैंकिंग प्रभाग, प्रधान कार्यालय, प्लाट सं. 4,
सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075

निविदा सूचना

पंजाब नैशनल बैंक "डेबिट एवं प्री-पेड कार्डों की आपूर्ति, प्रसंस्करण एवं पर्सनलाइजेशन" के लिए सेवा प्रदाताओं के दर अनुमोदन एवं चयन हेतु पात्र बोलीदाताओं से ऑनलाइन बिड (तकनीकी एवं वाणिज्यिक दोनों) आमंत्रित करता है।

इच्छुक बोलीदाता विस्तृत आरपीएफ दस्तावेज डाउनलोड करने के लिए हमारी ई-प्रोक्योरमेंट वैबसाइट **https://pnbindia.biz** अथवा **www.pnbindia.in** पर विजिट कर सकते हैं। बिड को हमारे ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम के माध्यम से डिज़िटल प्रमाणपत्र (हस्ताक्षर और इंक्रिप्शन दोनों) का उपयोग करते हुए ऑनलाइन जमा कराने की आवश्यकता है। ऑनलाइन बिड की तैयारियां एवं हैश (Hash) प्रस्तुतीकरण की अंतिम तिथि दिनांक 23.02.2018 को सायं 4:00 बजे तक है तथा बिड का प्रस्तुतीकरण दिनांक 24.02.2018 को अपराह्न 3:00 बजे तक है।

मुख्य प्रबंधक

एसपीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

पंजी. कार्याः सी-2/54, 5वीं मंजिल, राजस्थली अपार्टमेंट्स, पीतमपुरा, दिल्ली-110034
CIN: L74899DL1991PLC062744, **E-mail:** cs@spllimited.com
Website: www.spllimited.com

बोर्ड बैठक की सूचना

सेबी (सूचीबद्ध दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 47 के अनुपालन में, एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निदेशक मंडल की बैठक 31 दिसंबर, 2017 को समाप्त तिमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार करने और स्वीकृत करने के लिए सोमवार, 12 फरवरी, 2018 को आयोजित की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, (प्रोहेबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग) विनियम, 2015 के अनुपालन में प्रोहेबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट के अनुपालन में, कंपनी की प्रतिभूतियों में डीलिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो 03 फरवरी, 2018 से उपरोक्त वित्तीय परिणामों की घोषणा के उद्देश्य के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों को स्टॉक एक्सचेंजों में जमा किए जाने की तिथि के बाद 48 घंटों तक (दोनों दिन शामिल) कंपनी के सभी निदेशकों, अधिकारियों और कर्मचारियों व जुड़े व्यक्तियों के लिए बंद रहेगी।

एसपीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
आशीष यादव
(कंपनी सचिव व अनुपालक अधिकारी)

दिनांक : 02.02.2018
स्थान : फरीदाबाद

रिमरॉक प्रोजैक्ट्स एलएलपी

पंजी. कार्यालयः सी-23, ग्रेटर कैलाश एन्कलेव, पार्ट-I, नई दिल्ली-110048, भारत
फोन नं. 8059933283, ईमेल आईडीः- bansaldk75@gamil.com
एलएलपीआईएन एएबी-0387

सूचना

समक्ष कंपनी पंजीयक, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा, नई दिल्ली

सीमित देयता भागीदारी, 2008, एलएलपी अधिनियम, 2008 की धारा 13 के प्रावधानों और सीमित देयता भागीदारी नियमावली, 2009 के नियम 17 के अनुसार पठित, के मामले में

और

रिमरॉक प्रोजैक्ट्स एलएलपी (एलएलपीआईएन एएबी-0387) पंजीकृत कार्यालयः सी-23, ग्रेटर कैलाश एन्कलेव, पार्ट-I, नई दिल्ली-110048, भारत

आवेदक

एतद् द्वारा सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है कि उक्त एलएलपी अपने पंजीकृत कार्यालय को ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली'' से ''हरियाणा राज्य'' में स्थानांतरण के लिए 30.01.2018 को आयोजित पदनामित भागीदारों की बैठक में पारित संकल्प के अनुपालन में एलएलपी करार में परिवर्तन के अनुमोदन हेतु सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 के तहत केंद्र सरकार से प्रस्ताव करती है।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के उक्त पंजीकृत कार्यालय के ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली'' से ''हरियाणा राज्य'' में स्थानांतरण से प्रभावित होने की संभावना हो तो वह इस सूचना प्रकाशन के 21 दिनों के अंदर हित की प्रकृति और याचिका के प्रति अपने विरोध का आधार बताते हुए शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति कंपनी पंजीयक, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा, 4वां तल, आईएफसीआई टॉवर, 61 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 को सूचित करें और उपरोक्त पते पर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में उक्त एलएलपी की प्रतिलिपि सहित आपत्ति को मूल रूप में कंपनी पंजीयक, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा को भेजें।

बोर्ड के आदेशानुसार
रिमरॉक प्रोजैक्ट्स एलएलपी

(विशाल गर्ग)	(मीनाक्षी गर्ग)	(अनुराधा गर्ग)
पदनामित भागीदार	पदनामित भागीदार	पदनामित भागीदार
डीआईपीआईएन 01665920	डीआईपीआईएन 06634557	डीआईपीआईएन 06634562

दिनांक: 03-02-2018 **स्थान: नई दिल्ली**